University Education

903. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that State Governments are unable to meet the need of people for university education;

(b) whether it is a fact that a large number of students are unable to get university education in rural areas and small towns;

(c) whether Government have contemplated any new and innovative concepts to meet the present day demands of State Sector University education; and

(d) if so, the details of the concepts under cosideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (d) While it is difficult to generalise that the aspirations of a number of young persons to receive University education are unfulfilled, it is possible that the continued increase in population may be responsible for demands in certain areas.

The policy relating to extension of Distance Education System, both through open and conventional universities, and provision of non-collegiate educational system are the initiatives introduced to meet the aspirations of all to receive tertiary education.

रेलवे की केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों और राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया देय-राशि

904. **श्री अजीत जोगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों और राज्य विद्युत बोर्डों की ओर भारतीय रेलवे की करोड़ों रुपये की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने काफी समय से बकाया पड़ी धनराशि की वसूली के लिए इस वर्ष के दौरान इन विद्युत स्टेशनों और विद्युत बोर्डों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने इस संबंध में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) 30.9.96 को परियोजनावार विवरण:-

क्रम सं॰	राज्य विद्युत बोर्ड/ पावर हाउस का नाम	(करोड़ रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	29.97
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	6.91
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	3.94
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	86.31
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	10.86
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	71.00
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.07
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	31.35
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	4.14
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	37.97
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	1.19
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1.29
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	47.58
14.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	29.28
15.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र	711.12
16.	राष्ट्रीय ताप विद्युत नि.लि./अन्य	50.85
17.	प्राइवेट पावर हाउस – साबरमती	2.54
	जोड़ :	1126.37

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रि मंडल ने विनिश्चय किया है कि नई राशि देय होने को रोकने के उद्देश्य से सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत गृहों पर 1.10.96 से अदायगी योजना लागू की जानी चाहिए। यह योजना बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में 31.12.96 तक अस्थायी रूप से आस्थगित कर दी गई है। पिछली बकाया राशि की वापसी के संबंध में मंत्रिमंड़ल की उपयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के

अनुसार यह मामला सचिवों की समिति को भेजा गया है।

(ङ) जी हां।

(च) राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत गृहों के लिए दूसरा विकल्प यह है कि ये अग्रिम भुगतान योजना और केवल भार प्रणाली को लागू करें ताकि उनके विरूद्ध कोई बकाया राशि देय न हो।

मध्य प्रदेश सरकार की रेलवे पर बकाया देय-राशि

905. श्री राघवजी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे पुलिस की व्यवस्था के लिए रेलवे द्वारा उक्त सरकार को देय पचास प्रतिशत धनराशि में से 31 अक्टूबर 1996 तक की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि देय है;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को उपरोक्त धनराशि कब तक मुहैया करा दी जायेगी; और

(ग) उक्त राशि के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) इस समय रेलों के पास कुल, 5.00 करोड़ रुपए बकाया है। बहरहाल, रेलवे प्रशासन के अनुमोदन के बिना सरकारी रेलवे पुलिस के पदों के सृजन के कारण लगभग 11.53 करोड़ रु० का मध्य रेल द्वारा अस्वीकृत दावा इस राशि में शामिल नहीं है।

(ख) 1996-97 में स्पष्टत: अनुमेय बिलों को पास किया जाएगा। बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ग) भुगतान में विलंब के कारण निम्नानुसार है:-

(1) इस प्रयोजन हेतु बजटीय व्यवस्था की तंगी।

(2) रेल प्रशासन के बिना अनुमोदन के राज्य सरकारों द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस का एक पक्षीय सृजन।

Adolescent Girls Scheme in Gujarat

906. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that Adolescent Girls Scheme is being implemented in the State of Gujarat as an integral part of the Centrally sponsored Integrated Child Development Services (ICDS);

(b) if so, the details of the salient features of the scheme;

(c) the number of adolescent girls who have received vital services under the scheme in the State so far; and

(d) the steps Government propose to take to popularise the scheme in the State?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) yes, Sir. The adolescent Girls Scheme is bieng implemented in 15 selected Integrated Child Development Services (ICDS) projects in the State of Gujarat, as a special intervention in the ICDS Scheme.

(b) The Adolescent Girls Scheme aims at reaching out to the adolescent girls in the age group of 11-18 years for improving their nutritional and health status, providing required literacy and numeracy skills, improving and upgrading their home based skills and helping them to understand their reproductive roles.

(c) A total number of 42873 adolescent girls have been covered under the scheme in the State of Gujarat, till date.

(d) The Government have taken a number of initiatives including holding of State level workshop, District level workshops and organising various training activities at the Block level and at the sector levels with a view to popularise the scheme. And, accordingly, the scheme has had a very favourable response.

Rehabilitation Plant for Bhopal Gas Victims

907. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bhopal Gas tragedy victims are still drinking toxic water; and

(b) if so, the causes of failure of the rehabilitation plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) and (b) No Sir. According to the information received from the State Government of Madhya Pradesh, the laboratory reports obtained from time to time indicate that the drinking water being made available is safe for human consumption.